

4 December 2024

## एसोचौम-ईग्रो अध्ययन: एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियाँ और समाधान

**सन्दर्भ:** हाल ही में एसोचौम-ईग्रो द्वारा भारतीय एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) पर एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में एमएसएमई क्षेत्र की मुख्य चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत, इस क्षेत्र के विकास को समर्थन देने और उसकी भूमिका को सशक्त बनाने के लिए समाधान सुझाए गए हैं।

### एमएसएमई के समक्ष चुनौतियाँ:

- वित्तीय चुनौतियाँ:** एमएसएमई को पारदर्शी ऋण स्वीकृति प्रक्रियाओं तक पहुंच बनाने में कठिनाई होती है तथा उच्च ब्याज दरों और अप्रयुक्त ऋण शुल्कों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- अनुपालन चुनौतियाँ:** जीएसटी की जटिलता और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का बोझ एमएसएमई के लिए अनुपालन को कठिन बना देता है।

### प्रस्तावित समाधान:

- सरलीकृत जीएसटी:** एमएसएमई के लिए विनियामक बाधयता को कम करने के लिए अधिक सुव्यवस्थित जीएसटी प्रणाली की सिफारिश की गई है।
- कम टीडीएस:** अध्ययन में टीडीएस का बोझ कम करने के लिए केवल जरूरी भुगतानों पर कटौती और कुछ एमएसएमई के लिए टर्नओवर के आधार पर सरल कर प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया है।
- कॉर्पोरेट कर में कमी:** व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई के लिए कॉर्पोरेट आयकर की दर 25% से घटाकर 15% की जानी चाहिए।
- वित्तीय समाधान:** एमएसएमई-विशिष्ट बांड और म्यूचुअल फंड की शुरुआत की सिफारिश की गई है और लघु वित्त बैंकों का विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, ताकि वित्तीय तरलता में सुधार हो और अधिक से अधिक एमएसएमई को वित्तीय सहायता मिल सके।

### एमएसएमई के बहुआयामी विकास हेतु सुझाव:

- एमएसएमई-विशिष्ट संस्थान:** अध्ययन में प्रत्येक राज्य में एमएसएमई विश्वविद्यालयों के निर्माण की सिफारिश की गई है, ताकि अनुसंधान एवं विकास, वित्त, विपणन, और प्रशिक्षण जैसी व्यापक सहायता प्रदान की जा सके। इससे एमएसएमई की जरूरतों को पूरा करने और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

- कौशल विकास:** कौशल भारत मिशन को राज्य-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ उन्नत किया जाना चाहिए। एमएसएमई और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय की सिफारिश की गई है, ताकि एक कुशल कार्यबल का निर्माण हो सके, जो एमएसएमई विकास का समर्थन कर सके।
- बुनियादी ढांचा:** परीक्षण केंद्रों, वित्तीय संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों के साथ एकीकृत बुनियादी ढांचा टाउनशिप का विकास पूरे भारत में एमएसएमई समूहों को समर्थन प्रदान कर सकता है।

### एमएसएमई को परिभाषित करना:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और निर्यात में प्रमुख योगदान देते हैं।
- एमएसएमई का वर्गीकरण उनके संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश के आधार पर किया जाता है:
  - » **सूक्ष्म उद्यम:** 1 करोड़ तक का निवेश और 5 करोड़ तक का कारोबार।
  - » **लघु उद्यम:** 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार।
  - » **मध्यम उद्यम:** 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच निवेश और 250 करोड़ तक का कारोबार।

### भारत की आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई का महत्व:

- एमएसएमई भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% और निर्यात में 46% का योगदान करते हैं (वित्त वर्ष 2024 तक)।
- भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि 2047 तक 3.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 22.8 ट्रिलियन डॉलर हो जाने की संभावना है। इस आर्थिक परिवर्तन में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

## प्रगति प्लेटफॉर्म

**संदर्भ:** भारत के 'प्रगति' (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) प्लेटफॉर्म को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डिजिटल गवर्नेंस के एक परिवर्तनकारी उदाहरण के रूप में सराहा गया है।

- रिपोर्ट 'अवरोध से विकास तक: नेतृत्व किस प्रकार भारत के प्रगति परिस्थितिकी तंत्र को प्रगति की शक्ति प्रदान करता है', शासन में जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाते हुए बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने में प्रगति प्लेटफॉर्म की सफलता को प्रमुख रूप से रेखांकित करती है।

### प्रगति के बारे में:

## Face to Face Centres



4 December 2024

- प्रगति योजना, जोकि 2015 में शुरू की गई, परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यों में आने वाली रुकावटों को शीघ्र दूर करना और निगरानी को प्रभावी बनाना है।
- यह योजना समयबद्ध निर्णय लेने और प्रभावी निगरानी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वास्तविक समय डेटा और ड्रोन फीड जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग करती है।

### उद्देश्य:

- परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाना।
- अंतर-एजेंसी सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- जवाबदेही और शासन को मजबूत बनाना।



**PM launched PRAGATI platform**  
Pro-Active Governance & Timely Implementation

-  PM Modi reviews & monitors various schemes, grievances, state & central projects
-  Directly interacts with Secretaries of Centre & States through Video conferencing
-  Resolves issues to fast-track implementation and completion

### प्रमुख विशेषताएँ:

- **प्रौद्योगिकी-चालित:** वास्तविक समय डेटा और निगरानी का उपयोग करता है।
- **प्रत्यक्ष निरीक्षण:** यह प्रधानमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सीधे संपर्क को सक्षम बनाता है।
- **सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ:** बेहतर समन्वय के लिए प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया जाता है।

### आर्थिक प्रभाव:

- प्रगति योजना ने भारत की आर्थिक वृद्धि और लचीलापन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है:
  - » **गुणक प्रभाव:** प्रगति के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर

खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2.5 से 3.5 रुपये का लाभ हुआ है। यह आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने में प्रगति की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

- » **आर्थिक लचीलापन:** परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन ने भारत को वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया और देश की आर्थिक स्थिरता को मजबूत किया।
- » **बुनियादी ढांचे का विकास:** भूमि अधिग्रहण और अंतर-मंत्रालयी समन्वय जैसे जटिल मुद्दों का समाधान किया गया।
- परिवहन, ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी से प्रगति को सुनिश्चित किया गया।

### सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव:

- आर्थिक लाभ के अलावा, प्रगति ने सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है:
  - » **सामाजिक विकास:** सड़क, बिजली, पानी और रेलवे जैसी आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच। अविकसित क्षेत्रों में परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - » **पर्यावरणीय स्थिरता:** हरित प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने में प्रगति हुई। परियोजना नियोजन में पर्यावरण मंजूरी को सुव्यवस्थित किया गया और पर्यावरण अनुकूल उपायों को शामिल किया गया।

### वैश्विक स्तर पर अनुकरणीय मॉडल:

- प्रगति उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मापनीय और अनुकरणीय ढांचे के रूप में कार्य करती है, जोकि शासन नवाचार में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है:
  - » **शासन नवाचार:** दक्षता, सहयोग और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और नेतृत्व का संयोजन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश कैसे सतत विकास को बढ़ावा दे सकता है।
  - » **विकासात्मक चुनौतियों का समाधान:** यह देशों को नौकरशाही की अकुशलताओं पर काबू पाने और सतत विकास प्राप्त करने में मदद करता है। यह मध्यम आय से उच्च आय की स्थिति में संक्रमण के लिए व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है।

### निष्कर्ष:

प्रगति प्लेटफार्म शासन और प्रौद्योगिकी के सही संयोजन के माध्यम से विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। परियोजनाओं को तेजी से लागू करने, सहयोग को बढ़ावा देने और परिणाम देने में इसकी सफलता ने इसे प्रभावी शासन का एक वैश्विक मॉडल बना दिया है।

### Face to Face Centres



4 December 2024

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इसकी मान्यता प्राप्त होने के बाद, प्रगति सतत और समावेशी विकास के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाने वाले देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।

### भूमि क्षरण और उसके प्रभाव: एक वैश्विक चुनौती

**संदर्भ:** हाल ही में जारी हुई संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की रिपोर्ट 'स्टेपिंग बैक फ्रॉम द प्रीसिपिस: ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे विदिन प्लेनेटरी बाउंड्रीज' भूमि क्षरण की बढ़ती समस्या और इसके प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त करती है।

#### रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **वार्षिक क्षरण:** प्रत्येक वर्ष लगभग दस लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षरण हो रहा है।
- **कुल प्रभावित क्षेत्र:** लगभग 15 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पहले ही भूमि क्षरण से प्रभावित हो चुका है, जोकि अंटार्कटिका के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है।

#### भूमि क्षरण क्या है?

- भूमि क्षरण का तात्पर्य भूमि की जैविक या आर्थिक उत्पादकता और जटिलता में गिरावट से है। यह विभिन्न प्रकार की भूमि को प्रभावित करता है, जिनमें शामिल हैं:
  - » वर्षा आधारित और सिंचित फसल भूमि
  - » चारागाह
  - » वन एवं वुडलैंड्स

#### भूमि क्षरण के परिणाम:

- **खाद्य सुरक्षा:** खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में कमी के कारण कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है।
- **स्वास्थ्य जोखिम:** अपर्याप्त स्वच्छता और जल की कमी के कारण जल-जनित एवं खाद्य जनित बीमारियाँ फैलती हैं।
- **श्वसन संबंधी समस्याएं:** धूल भरी आंधी और मिट्टी के कटाव से श्वसन संबंधी बीमारियाँ बढ़ती हैं।
- **पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान:** मिट्टी अपरदन से निकलने वाली मिट्टी, उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे रसायनों के साथ मिलकर जल निकायों में पहुँच जाती है, जिससे जलीय जीवन और इन जल स्रोतों पर निर्भर समुदायों को नुकसान पहुँचता है।

#### जलवायु परिवर्तन में योगदान

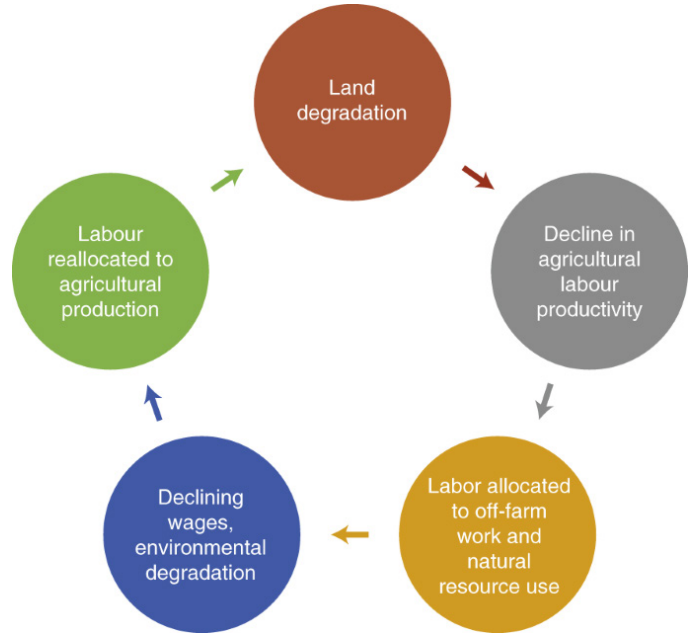
- **कार्बन उत्सर्जन:** क्षरित मिट्टी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और

नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ती है।

- **कार्बन सिंक क्षमता में कमी:** भूमि पारिस्थितिकी तंत्रों, जैसे वृक्ष और मिट्टी, की मानव-जनित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता में पिछले दशक में 20% की कमी आई है।

#### भूमि क्षरण के कारण:

- **असंवहनीय कृषि:** रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खराब सिंचाई प्रथाओं के अत्यधिक उपयोग से वनों की कटाई, मृदा क्षरण और प्रदूषण होता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** अत्यधिक वर्षा और तापमान तनाव जैसी चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति से भूमि क्षरण की स्थिति और खराब हो जाती है।
- **शहरीकरण:** तेजी से हो रहा शहरी विस्तार आवास विनाश और प्रदूषण में योगदान देता है, जिससे भूमि क्षरण में तेजी आती है।



#### भौगोलिक हॉटस्पॉट

- **शुष्क भूमि क्षेत्र:** दक्षिण एशिया, उत्तरी चीन, अमेरिका के उच्च मैदान और भूमध्य सागर को हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है।
- **निम्न आय वाले देश:** ये क्षेत्र भूमि क्षरण के प्रभावों को झेलने की कम क्षमता के कारण असमान रूप से प्रभावित हैं।

#### निष्कर्ष

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भूमि क्षरण को परिवर्तनकारी भूमि प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। प्रमुख रणनीतियाँ निम्नलिखित हैं:

#### Face to Face Centres



4 December 2024

- » **टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ:** रासायनिक इनपुट को कम करना, सिंचाई विधियों में सुधार करना और वनों की कटाई को रोकना।
- » **जलवायु परिवर्तन शमन:** चरम मौसम की घटनाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना।
- » **संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण:** निम्न आय वाले देशों के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जो सबसे अधिक जोखिम में हैं।

### रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया

**सन्दर्भ:** हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश में रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है।

#### रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में :

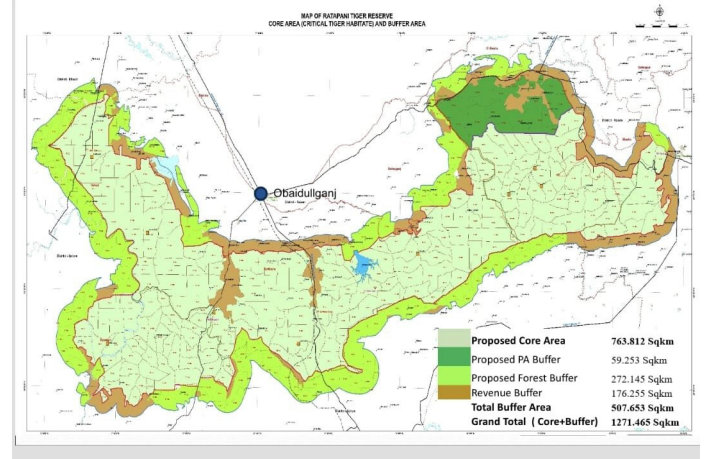
- रायसेन जिले में विन्ध्य पहाड़ियों में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1,271.4 वर्ग किलोमीटर है। इसमें शामिल हैं:
  - » मुख्य क्षेत्र: 763.8 वर्ग किलोमीटर
  - » बफर क्षेत्र: 507.6 वर्ग किलोमीटर
- यह अभयारण्य विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का घर है, जिनमें सागौन के वन प्रमुख हैं।
- इसके अतिरिक्त, यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है क्योंकि इसमें कई अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के साथ-साथ भीमबेटका रॉक शैल्टर्स, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, भी शामिल है।
- यह अभयारण्य भोपाल से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, जिससे यह इकोटूरिज्म के लिए एक सुलभ और आकर्षक स्थान बन गया है।

#### विधायी ढांचा और स्थानीय समुदायों के अधिकार:

- रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ट के तहत आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह कानून महत्वपूर्ण बाघ आवासों की पहचान करता है और संरक्षण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें कोर और बफर जोन में अलग करता है।
- इस निर्णय के तहत 26.947 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले नौ गांवों को बफर जोन में शामिल किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभयारण्य में रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, जिससे वन्यजीव संरक्षण और समुदाय की भलाई के बीच संतुलन बना रहेगा।

#### संरक्षण और विकास के लिए निहितार्थ:

- **संवर्धित संरक्षण प्रयास:** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) से वित्तीय सहायता मिलने से वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण उपायों को मजबूत किया जा सकेगा।
- **इको-टूरिज्म को बढ़ावा:** टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
- **पारिस्थितिक विकास कार्यक्रम:** क्षेत्र में आजीविका सुधार और सतत विकास के लिए नए कार्यक्रमों को समर्थन मिलेगा, जिससे सामाजिक और आर्थिक उन्नति संभव हो सकेगी।



#### मध्य प्रदेश: बाघ संरक्षण में अग्रणी

- रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने के साथ ही, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या आठ हो गई है। राज्य पहले से ही बाघ संरक्षण में अग्रणी है और यह कदम उसकी बाघों के आवास विस्तार और पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में NTCA ने शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति दे दी है।

#### निष्कर्ष:

रातापानी वन्यजीव अभयारण्य का टाइगर रिजर्व के रूप में उन्नयन, भारत में वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कदम न केवल जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय समुदायों के आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को भी सुरक्षित रखते हुए सतत संरक्षण का आदर्श स्थापित करेगा।

Face to Face Centres



4 December 2024

### पाँवर पैकड न्यूज

#### हरिमऊ शक्ति अभ्यास

- 'हरिमऊ शक्ति' अभ्यास का चौथा संस्करण मलेशिया के पहांग स्थित बेंटोंग शिविर में शुरू हुआ, जो भारत-मलेशिया सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच प्रतिवर्ष चक्रीय आधार पर आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अध्याय VII के अनुसार, जंगल क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों में दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है।
- इस वर्ष, भारतीय दल, जिसका प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन करेगी, प्रशिक्षण के दो चरणों में भाग लेगा। पहले चरण में व्याख्यान, प्रदर्शन और जंगल क्षेत्र में अभ्यास के साथ क्रॉस-ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- दूसरे चरण में कृत्रिम अभ्यास शामिल होगा, जिसमें दोनों सेनाएं एंटी-एमटी एंबुश (Anti-Mine Trap Ambush), रेकी गश्त और आतंकवाद विरोधी हमलों जैसे ऑपरेशनों का अभ्यास करेंगी।
- यह अभ्यास, जोकि भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होता है, दोनों पक्षों को सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने, अंतर-संचालन में सुधार लाने तथा सौहार्द को बढ़ावा देने का एक मंच प्रदान करता है। उमरोई छावनी में आयोजित पिछले संस्करण ने सैन्य सहयोग को गहरा करने, आपसी विश्वास का निर्माण करने और आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों में परिचालन तत्परता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

#### अर्जुन एरिगैसी ने 2800 ELO रेटिंग हासिल कर शतरंज में नया इतिहास रचा

- अर्जुन एरिगैसी, वारंगल (तेलंगाना) के शतरंज खिलाड़ी, ने 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। 1 दिसंबर, 2024 को एरिगैसी की रेटिंग 2801 हो गई, जिससे वह दुनिया में चौथे स्थान पर आ गए। वह यूएसए के हिकारू नाकामुरा से सिर्फ एक अंक पीछे हैं, जिनकी रेटिंग 2802 है।
- एरिगैसी की यह उपलब्धि पांच बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद, जोकि 2800 रेटिंग तक पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, के बाद आई है। अर्जुन एरिगैसी अब इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले विश्व के 16वें खिलाड़ी हैं।
- अपनी व्यक्तिगत सफलता के अतिरिक्त, एरिगैसी ने हाल ही में शतरंज ओलंपियाड में एक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक और एक टीम खिताब जीता। उन्होंने अपना ग्रैंडमास्टर खिताब केवल 14 साल, 11 महीने और 13 दिन की उम्र में हासिल किया।
- एक अन्य प्रतिभाशाली भारतीय खिलाड़ी डी. गुकेश 2783 की रेटिंग के साथ पांचवे स्थान पर हैं। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन 2831 की रेटिंग के साथ अभी भी दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी हैं, उनके बाद अमेरिका के फैंबियानो केरुआना 2805 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।



#### Face to Face Centres

